IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 1, November 2025 Impact Factor: 7.67

आर्थिक विकास एवं नगरीयकरण ग्वालियर एवं इन्दौर महानगर का तुलनात्मक अध्ययन

विक्रम यादव

शोधार्थी, वाणिज्य विभाग सनराइज विश्वविद्यालय अलवर (राजस्थान)

डॉ. रामबीर

शोध मार्गदर्शक, सहायक प्राध्यापकवाणिज्य विभाग सनराइज विश्वविद्यालय अलवर (राजस्थान)

प्रस्तावना– नगरीकरण आर्थिक विकास का पर्याय माना जाता है किन्तु नगरीकरण आर्थिक विकास के लिये एक प्रकार से चुनौती भी है। तेजी से बढ़ती नगरों की जनसंख्या के कारण नगरों पर जनसंख्या का दबाव बढ़ने से नगरों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं पर दबाव बढ़ता है। फलतः यह बढ़ती हुई नगरीय जनसंख्या नगरों के लिये समस्या मूलक बनती जा रही है। आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, ठोस कचरा प्रबन्धन, जल आपूर्ति, जलभराव, यातायात, मलजल निकास, अपराध बढ़ना इत्यादि समस्यायें स्थानीय नगरीय प्रशासन के लिये बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। शोध कार्य में इन्हीं प्रश्नों पर विचार करते हुये नगरीकरण की प्रवृति, नगरीकरण जनित समस्याओं तथा उनके समाधान के उपायों का विश्लेषण किया गया है।

शोधपत्र ग्वालियर, इन्दौर राज्य में नगरीकरण के फलस्वरूप नगरों में उत्पन्न होने वाली मूलभूत सुविधाओं सम्बन्धी समस्याओं के अध्ययन पर आधारित है। इसके अन्तर्गत ग्वालियर, इन्दौर के ग्वालियर तथा इन्दौर नगरों का विशेष रूप से अध्ययन करके चयनित नगरीकरण की समस्याओं का विश्लेषण किया गया है तथा इन चयनित दो नगरों की नगर पालिका सीमा के अन्तर्गत आने वाली जनसंख्या तथा उसकी प्रमुख चार समस्याओं (1) ठोस कचरा प्रबन्धन (2) जल आपूर्ति (3) जलभराव तथा (4) महानगरीय यातायात व्यवस्था का अध्ययन हेतु चुना गया है।

शोध कार्य के उद्देश्य – विचाराधीन शोध कार्य का प्रमुख उद्देश्य ग्वालियर, इन्दौर में नगरीकरण की प्रवृति ज्ञात करना, उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अध्ययन करना तथा उनके समाधान हेतु नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना है। शोध कार्य को परिणाममूलक तथा उपयोगितामूलक बनाने हेतु निम्न वशिष्ट उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं –

- ग्वालियर नगर की नगरीकरण की प्रवृति ज्ञात करना।
- ग्वालियर तथा इन्दौर नगरों की चयनित मूलभूत नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता ज्ञात करना।

शोध प्रविधि – शोधपत्र ग्वालियर, इन्दौर राज्य की नगरीकरण की प्रवृति से सम्बन्धित है। इसमें नगरीकरण की प्रवृति के रूप में तेजी से बढ़ती नगरीय जनसंख्या का विश्लेषण किया गया है तथा तेजी से बढ़ती नगरीय जनसख्या के कारण नगरों में उत्पन्न होने वाली मूलभूत सुविधाओं का विश्लेषण किया गया है। इन मूलभूत सुविधाओं के रूप में चार समस्याओं का चयन किया गया है –1. ठोस कचरा प्रबन्धन 2. जल आपूर्ति 3. जलभराव तथा 4. महानगरीय यातायात व्यवस्था। इन चयनित चारसमस्याओं के सम्बन्ध में विश्लेषण हेतु राज्य के दो नगरों ग्वालियर तथा इन्दौर का चयन किया गया है। इन चयनित दो नगरों से चयनित समस्याओं का विश्लेषण करने हेतु दोनों नगरों की नगर पालिकाओं द्वारा किये गये कार्यों की प्रगति का विश्लेषण किया गया है।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 1, November 2025 Impact Factor: 7.67

यह विश्लेषण वर्ष 2015–16 से 2020–21 तक छह वर्ष की अवधि से सम्बन्धित है जिससे नगरीकरण की प्रवृति का विश्लेषण तथा चयनित समस्याओं के समाधान की प्रगति का विश्लेषण द्वितीय समंकों पर आधारित है जबकि चयनित समस्याओं का विश्लेषण प्राथमिक समंकों पर आधारित है।

इस प्रकार शोध कार्य में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के समंकों के आधार पर ग्वालियर, इन्दौर राज्य में नगरीकरण एवं उससे उत्पन्न होने वाली मूलभूत समस्याओं का विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर इन समस्याओं के समाधान हेतु नीतिगत सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं।

शोध साहित्य का पुनरावलोकन – कुछ प्रमुख पूर्ववर्ती शोध कार्यों का विवरण इस प्रकार है। चेतन वैध (2009) ने अपने वार्किंग पेपर क्र. 04/2009 डी.ई.ए. आर्थिक मामले विभाग, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, अरबन इश्यू, रिफार्म एण्ड वे फारवर्ड इन इण्डिया में भारत में नगरीकरण की समस्या का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। इसके अन्तर्गत उन्होंने नगरों की प्रमुख समस्याओं का विश्लेषण करने के साथ–साथ उनके समाधान के सुझाव भी प्रस्तुत किये हैं। उन्होंने स्थानीय निकायों में क्षमता निर्माण, कार्य प्रणाली में सुधार समन्वित नगरीय यातायात प्रणाली, नगरीय संस्थाओं का सशक्तीकरण तथा उनकी निश्चित भूमिका निर्धारित करने का सुझाव दिया है। इसके साथ स्थानीय नगरीय संस्थाओं में द्वितीय पीढ़ी के सुधारों के अन्तर्गत संस्थाओं का नियमन, वित्त के नवीन सातों की खोज, सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी एवं पर्यावरण संरक्षण के उपाय सुनिश्चित करने का सुझाव दिया है। संस्थाओं में कुशलता लाने तथा क्षमता निर्माण हेतु आपने स्थानीय राज्य स्तर तथा राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय बनाने तथा संवैधानिक एवं प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया है। शोध से संबंधित साहित्य की दृष्टि से श्री आर. बी. भगत (2011) का विश्लेषण इमरजिंग पैटर्न ऑफ अर्बनाईजेशन इन इण्डिया इकनामिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली अगस्त 20,2011,Vol-XLUI1 to 34,अत्यन्त महत्वपूर्ण है।इस सम्बंध में ए.एस. कादी बी.आई. हालिंगली तथा पी. शविशंकर (2012) इन्टरनेशनल जरनल ऑफ साईन्स एण्ड नेचर में प्रोबलम्स ऑफ अर्वनाईजेशन इनडवलपिंग कन्ट्रीज ए केस स्टडी ऑफ इण्डिया में बताया कि 1951 में 17% की दर से नगरीकरण हो रहा था। 2001 में नगरीकरण की दर बढ़कर 28% हो गई है। 2030 में यह बढ़कर 41% होने की संभावना है जिसके फलस्वरूप आवास, जल निकास, जल आपूर्ति तथा नगरीय यातायात की समस्या पैदा हो रही है।

इस संबंध में विनोद कुमार भापो (2010) का इम्पेक्ट एसेसमेन्ट ऑफ प्रोजेक्ट उत्थान इन भोपाल, एन. राय एवं ए.सिंह (2011) की पुस्तक न्यू डायमेन्सन्स ऑफ अरबन मैनेजमेंट इन इण्डिया, एम.ए. मेगरी (2002) का प्रोसेज ऑफ अर्वनाईजेशन ए. स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, मुकेश कपूर (2002) का विजन 2020 ट्रान्सपोर्ट, इत्यादि भी उल्लेखनीय है।

ग्वालियर, इन्दौर में नगरीकरण की प्रवृति –

नगरीकरण विकास का सूचक होने के साथ–साथ विकास के लिये चुनौती भी है। ग्वालियर, इन्दौर विशाल और तीव्र गति से बढ़ती नगरीय जनसंख्या वाला प्रदेश है। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर प्रदेश की कुल 7,25,17,565 जनसंख्या में से 2,00,59,666 जनसंख्या प्रदेश के विभिन्न नगरों में निवास करती है, जो कुल प्रादेशिक जनसंख्या का 27.6% है। प्रदेश में एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले कुल 33 नगर है। प्रदेश में चार महानगरों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। इन्दौर नगर की जनसंख्या 21,67,447 भोपाल नगर की जनसंख्या 18,83,381 जबलपुर नगर की जनसंख्या 12,67,564 तथा ग्वालियर

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 1, November 2025 Impact Factor: 7.67

नगर की जनसंख्या 11,01,981 है। प्रदेश की यह नगरीकरण की प्रवृति एक ओर आर्थिक विकास की प्रवृति सूचित करती है तो वहीं दूसरी ओर आर्थिक विकास के लिये चुनौतियां उत्पन्न करती है।

विगत वर्षों में प्रदेश में तीव्र नगरीकरण की प्रवृति परिलक्षित हुई है। प्रदेश की नगरीय जनसंख्या में निरन्तर तीव्रगति से वृद्धि हो रही है। नगरों की संख्या और नगरीय जनसंख्या दोनों ही दृष्टियों से प्रदेश में वृद्धि की प्रवृति परिलक्षित हो रही है। ऐतिहासिक दृष्टि से तथा समकालीन दृष्टि से प्रदेश में निरन्तर नगरीकरण की प्रक्रिया जारी है। 1901 में प्रदेश में 97 नगर ग्रेड–एथे जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् बढ़कर 167 हो गये। 1971 में प्रदेश में नगरों की संख्या 190 थी। इसके पश्चात् निरन्तर वृद्धि की प्रवृति रही। 1981 प्रदेश में नगरों की संख्या 253 हो गई और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 1901 को 10.49 की तुलना में बढ़कर 22.34 हो गया। 2001 में प्रदेश में नगरों की संख्या बढ़कर 368 हो गई और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 26. 67 हो गया। प्रदेश में वर्तमान में (2011) की जनगणना के अनुसार 476 नगर है और 27.6% जनसंख्या प्रदेश के नगरों में निवास करती है।

तालिका क्रमांक–1

ग्वालियर, इन्दौर में नगरीरय करण

वर्ष	नगरों की संख्या	कुल संख्या	नगरीय जनसंख्या	नगरीय जनसंख्या का %	नगरीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर(प्रतिशत में)
1901	97	12679214	1329445	10–49	–
1911	98	14249382	1172290	8–23	11–82
1921	99	13906774	1277021	9–18	8–93
1931	118	15326879	1565868	10–22	22–62
1941	138	17175722	2058412	11–98	31–46
1951	167	18614981	2768988	14–87	34–52
1961	171	23217910	3864520	16–64	39–57
1971	190	30016625	5576875	18–58	44–31
1981	253	38168507	8528287	22–34	52–92
1991	350	18566242	12274144	25–27	43–92
2001	368	30385118	16102510	26–67	31–19
2011	476	72597565	20059666	27–60	24–6

शोध में चयनित ग्वालियर एवं इन्दौर नगरों में नगरीकरण की प्रवृति प्रादेशिक नगरीकरण की प्रवृति से बहुत अधिक तीव्र है। दोनों नगरों में नगरीय जनसंख्या का अनुपात भी प्रादेशिक औसत अनुपात से बहुत अधिक है। ग्वालियर–इन्दौर महानगरों में नगरीकरण की प्रवृति – विचाराधीन शोध के अन्तर्गत ग्वालियर, इन्दौर में नगरीकरण की समस्याओं का अध्ययन करने हेतु प्रदेश के दो जिलों – ग्वालियर तथा इन्दौर का अध्ययन किया गया है। ग्वलियर तथा इन्दौर ग्वालियर, इन्दौर राज्य को दो अत्यन्त महत्वपूर्ण जिले हैं। ग्वालियर जिला औद्योगिक विकास के साथ–साथ सेवा क्षेत्र शिक्षा में अधिक विकसित जिला है जबकि इन्दौर जिला सेवा क्षेत्र शिक्षा के साथ–साथ औद्योगिक विकास की दृष्टि से विकसित जिला है। यही कारण है कि

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 1, November 2025 Impact Factor: 7.67

ग्वालियर जिले की अपेक्षा इन्दौर जिले में कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात अधिक है। ग्वालियर जिले की कुल जनसंख्या 20,32,036 है। इसमें 62.69% जनसंख्या नगरीय जनसंख्या है। ग्वालियर महानगर की जनसंख्या 10,90,327 है जो जिले की कुल जनसंख्या का 53.66% है तथा जिले की कुल नगरीय जनसंख्या का 85.6% है अर्थात् जिले की कुल जनसंख्या का 53.66% भाग ग्वालियर नगर निगम की सीमा में निवास करता है और ग्वालियर जिले की कुल नगरीय जनसंख्या का 85. 6% भाग ग्वालियर नगर निगम सीमा में निवास करता है।

तालिका क्रमांक–2

शोध क्षेत्र एवं प्रदेश में नगरीकरण की प्रवृत्ति

क्षेत्र / नगरीकरण	कुल जनसंख्या	नगरीय जनसंख्या	नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत	ग्रामीण जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत
ग्वालियर	20,32,036	12,73,792	62.69	7,58,244	37.31
इन्दौर	32,27,697	24,27,709	74.09	7,99,988	25.91
शोध क्षेत्र	52,59,733	37,01,501	70.37	15,58,232	29.63
ग्वालियर, इन्दौर	7,25,97,565	2,00,59,666	27.63	5,25,37,232	72.37

इस प्रकार जिले की 53.6% जनसंख्या को मूलभूत नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व ग्वालियर नगर निगम पर है और जिले की 85.6% नगरीय जनसंख्या को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने का दायित्व ग्वालियर नगर निगम का है। जो कि ग्वालियर नगर निगम के लिये बहुत बड़ी चुनौती है। लगभग 11 लाख लोगों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराना बहुत कठिन कार्य है।

इसी प्रकार, शोध क्षेत्र के दूसरे जिले इन्दौर की स्थिति है। इन्दौर जिले की कुल जनसंख्या 32,27,697 है जिसमें 74.09 नगरीय जनसंख्या है और इन्दौर नगर की जनसंख्या 19,60,631 है। इन्दौर नगर की जनसंख्या जिले की कुल जनसंख्या का 60. 74% है तथा जिले की कुल नगरीय जनसंख्या का 80.76 प्रतिशत है अर्थात् जिले की कुल जनसंख्या 60.74% भाग इन्दौर नगर निगम सीमा में निवास करता है और जिले की कुल नगरीय जनसंख्या का 80.76% भाग इन्दौर नगर निगम सीमा में निवास करता है।

इस प्रकार, जिले की 60.74% जनसंख्या को मूलभूत नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराने का दायित्व इन्दौर नगर निगम पर है और जिले की 80.87% नगरीय जनसंख्या को मूलभूत नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराने का दायित्व इन्दौर नगर निगम का है। यह इन्दौर नगर निगम के लिये बहुत बड़ी चुनौती है। 19 लाख से अधिक लोगों को मूलभूत नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराना बहुत कठिन कार्य हैं।

विचाराधीन शोध क्षेत्र के दूसरे जिले इन्दौर के नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली मूलभूत नागरिक सुविधाओं में से जल आपूर्ति, ठोस कचरा प्रबन्धन, जल निकासी प्रणाली तथा महानगरीय यातायात व्यवस्था सम्बन्धी चार प्रमुख समस्याओं का अध्ययन किया गया है।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 1, November 2025 Impact Factor: 7.67

नगरीकरण की प्रमुख समस्यायें–

नगरीकरण आर्थिक विकास का सूचक है। औद्योगिक नगरों की स्थापना आर्थिक विकास का कारण एवं परिणाम दोनों हैं। परन्तु तीव्र गति से ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का आगमन और आकर नगरों में बसना नगरीय क्षेत्रों में मूलभूत नागरिक सुविधाओं की मांग और पूर्ति में असन्तुलन उत्पन्न करता है। अतएव नगरीकरण के फलस्वरूप नगरीय क्षेत्रों में मूलभूत नागरिक सेवाओं की तेजी से मांग बढ़ती है किन्तु मांग के अनुरूप पूर्ति न हो सकने के कारण समस्या उत्पन्न होती है। तीव्र गति से बढ़ती मूलभूत नागरिक सुविधाओं की मांग योजनाकारों तथा स्थानीय नगरीय प्रशासन के लिये अनेक प्रकार की चुनौतियां उत्पन्न करता है। ठोस कचरा प्रबन्धन नगरीकरण की सबसे गम्भीर समस्या है। ठोस कचरा प्रबन्धन की उचित व्यवस्था न होने से गम्भीर बीमारियां उत्पन्न होती हैं जिसके परिणामस्वरूप निजी व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक बजट असन्तुलित होता है। बीमारी उत्पन्न होने से अस्वस्थ लोगों को एकओर कार्य से अवकाश लेना होता है तो दूसरी ओर कार्यक्षमता घटती है, जो उत्पादकता को घटाती है। शासन को विकास कार्यों हेतु निर्धारित बजट स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च करना होता है। इस प्रकारए ठोस कचरा प्रबन्धन की समस्या निजी व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक दोनों स्तरों पर गंभीर समस्या है और इसके विकास पर दूरगामी बहुआयामी नकारात्मक प्रभाव परिलक्षित होते हैं। गंदगी फैलने से एक ओर तो बीमारियां फैलती हैं वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य सेवाओं की मांग बढ़ती है। सफाई की कमी से बीमारियां जन्म लेती हैं और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता की कमी से लोग बार–बार बीमार होते हैं। इससे लोगों की कार्यक्षमता घटती है और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव होता है। साथ ही प्रशासन का विकास व्यय इन समस्याओं का हल करने में व्यय होता है। जिसमें एक प्रमुख आवास की समस्या है। नगर निगम क्षेत्र में बसने वाली सम्पूर्ण जनसंख्या को उपयुक्त आवास उचित कीमत पर उपलब्ध कराना बहुत बड़ी समस्या है। चयनित दोनों नगरों (ग्वालियर एवं इन्दौर) में आवासीय भूमि बहुत कम एवं सीमित है। पुराने आवासों में चौड़ी सड़क, पेयजल, जल निकास एवं सीवेज प्रणाली का अभाव होने के कारण लोग नये आवासीय क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, जहाँ उन्हें चौड़ी सड़कें, पेयजल, जल–मल निकास, अच्छे पर्यावरण, खुलेपन तथा अन्य सफाई एवं सुरक्षा जैसी सुविधायें उपलब्ध है किन्तु भूमि सीमित होने के कारण कृषि भूमि का आवासीय भूमि में रूपान्तरण स्वयं कृषि विकास एवं खाद्य सुरक्षा के लिये बड़ी चुनौती है। साथ ही इन क्षेत्रों में आवासों की निरन्तर कीमतें बढ़ने से सामान्य नागरिक की पहुँच से बाहर होते जा रहे हैं।

नगरीकरण की एक महत्वपूर्ण समस्या पेयजल आपूर्ति की समस्या है। पेयजल आपूर्ति की समस्या के दो पक्ष हैं– एक पेयजल की आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति हो तथा दूसरा पक्ष– जो पेयजल प्रदाय किया जाय वह– स्वच्छ हो जिससे उसका स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न हो। अपर्याप्त पेयजल आपूर्ति भी एक समस्या है तो गंदा पेयजल बीमारियों को जन्म देकर नई समस्या उत्पन्न करता है।

नगरीय क्षेत्रों में एक बड़ी समस्या स्थानीय परिवहन सुविधाओं की होती है। स्थानीय नगरीय परिवहन सुविधा एक बहुआयामी विचार है जिसमें नगर के सभी क्षेत्रों में i सार्वजनिक परिवहन के साधनों की उपलब्धता ii समय पर उपलब्धता iii उचित किराये पर उपलब्धता iv सुरक्षा दुर्घटना के सुरक्षा v महिलाओं की सुरक्षा vi चोरी–लूट से सुरक्षा तथा vii आरामदायक परिवहन के साधन, इसके साथ–साथ सड़क पार करने हेतु ओवर ब्रिज तथा अण्डर ब्रिज होना, जिससे आसानी से सड़क पार की जा सके और सड़क पार करने में दुर्घटना न हो।

नगरीकरण की अन्य महत्वपूर्ण समस्याओं में नगरीय शिक्षा व्यवस्था, नगरों में विद्युत आपूर्ति की समस्या, निचली बस्तियों में जलभराव की समस्या, बरसात के समय जल निकासी की समस्या, सार्वजनिक स्थलों–सड़कों एवं पार्को में प्रकाश एवं सफाई की समस्या कुछ ऐसी समस्यायें हैं। जिनका नगरों में रहने वाली जनसंख्या को सामना करना होता है। साथ ही स्थानीय नगरीय

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 1, November 2025 Impact Factor: 7.67

सरकारों का व्यय का बहुत बड़ा भाग विकास योजनाओं के स्थान पर इन समस्याओं के समाधान पर व्यय होता है। शोध क्षेत्र के चयनित ग्वालियर तथा इन्दौर नगरों की स्थानीय सरकारों को इन्हीं समस्याओं का समाधान करने की बहुत बड़ी चुनौती है।

निष्कर्ष

ग्वालियर, इन्दौर राज्य एवं इसके चयनित ग्वालियर एवं इन्दौर दोनों नगरों में तीव्र गति से नगरीकरण होने की प्रवृति परिलक्षित होती है। इसके कारण दोनों नगरों सहित प्रदेश में एक ओर विकास की प्रवृति देखी गई है, वहीं दूसरी ओर आवास, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, गंदगी, जल–मल निकास, जल–भराव, सार्वजनिक सुरक्षित परिवहन, ठोस कचरा प्रबन्धन जैसी मूलभूत नागरिक सुविधाओं की समस्यायें उत्पन्न हो गई हैं जो स्थानीय नगरीय शासन के लिये गम्भीर चुनौतियां हैं। ठोस कचरा प्रबन्धन की उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था, स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल आपूर्ति, जल–मल निकास की उचित व्यवस्था, जलभराव की समस्या के समाधान हेतु उपयुक्त नालियों का प्रबन्ध करके, सर्वसुलभ, आरामदायक, समयबद्ध तथा सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली विकसित करके कुछ सीमा तक नगरीयकरण के उत्पन्न समस्याओं का संकट कम किया जा सकता है। इस कार्य हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के साथ–साथ निजी क्षेत्र तथा जनभागीदारी की भी आवश्यकता है। दूसरी ओर नगरीकरण की तीव्रता कम करने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि तथा सहायक उद्योगों को विकसित करके ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के स्थायी अवसर बढ़ाये जा सकते हैं जिससे रोजगार की खोज में ग्रामीण जनसंख्या का नगरों की ओर पलायन कुछ सीमा तक रूकने की संभावना है। इस प्रकार,ग्वालियर, इन्दौर राज्य में नगरीकरण से उत्पन्न मूलभूत नागरिक समस्याओं के समाधान हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाकर तथा नगरीय क्षेत्रों में मूलभूत नागरिक सुविधाओं को बढ़ाकर प्रयास किये जा सकते हैं।

समाधान –

नगरीकरण की समस्याओं के समाधान हेतु दो प्रकार से प्रयास किये जा सकते हैं, प्रथम–नगरीकरण की प्रवृति को कम करके तथा द्वितीय–नगरीय क्षेत्रों में मूलभूत नागरिक सुविधाओं का विस्तार करके।

नगरीकरण की प्रवृति पर नियंत्रण करने हेतु –

ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देकर भी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाये जा सकते हैं। कृषि उत्पादों के सहायक उद्योग लगाकर भी रोजगार के अवसर बढ़ाये जा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक शिक्षा, सफाई, पर्यावरण संरक्षण, जल आपूर्ति, गोबर गैस प्लांट, सौर्य ऊर्जा कार्यक्रम तथा सड़क, भवन, तालाब, कुआ आदि के निर्माण की व्यवसायिक प्रणाली विकसित करके भी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाये जा सकते हैं। डेयरी तथा कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, मांस उत्पादन इत्यादि द्वारा भी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर जनित करके जनसंख्या को नगरों में जाने से रोका जा सकता है।

नगरीय क्षेत्रों में मूलभूत नागरिक सुविधाओं में वृद्धि करके –

सस्ते आवास, स्वच्छ पेयजल, साफ–सफाई, जल–मल निकास की उपयुक्त प्रणाली, पर्याप्त, समयबद्ध, और सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार कुछ ऐसे प्रमुख कार्य हैं जिन पर स्थानीय सरकारें काम करते हुये आगे बढ़कर नगरीकरण की समस्याओं के समाधान की दिशा में आगे बढ़ सकती है।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 1, November 2025
Impact Factor: 7.67

संदर्भ

[1]. जिला सांख्यिकी पुस्तिका 2019–20 जिला सांख्यिकी कार्यालय जिला ग्वालियर।

[2]. जिला सांख्यिकीय पुस्तिका 2010–11 से 2020–21 तक जिला सांख्यिकीय कार्यालय जिला इन्दौर।

[3]. जन सम्पर्क कार्यालय, जिला ग्वालियर म0प्र0 शासन, मोतीमहल ग्वालियर।